I/179426/2024

संख्या : 34 /XXV-/2023

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
5–मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक ~~26 दिसम्बर~~ 03 जनवरी, 2024

विषय : **General Election to House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim-Transfer/Posting of Officers-regarding.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा लोक सभा एवं आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा सिक्किम राज्यों की वर्तमान विधान सभाओं का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 16 जून, 2024, 11 जून, 2024, 02 जून, 2024 24 जून, 2024 तथा 02 जून, 2024 को समाप्त पर लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित एवं सम्पादित कराए जाने के दृष्टिगत निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबंध में नीति निर्धारित करते हुए निम्न प्रकार निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुसरण करना है कि, निर्वाचनाधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन से सीधी जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जनपद या उन स्थानों पर तैनात न किया जाए, जहॉ उन्होंने अत्यधिक लम्बे समय तक सेवा की है।

3– उक्त के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी को, वर्तमान जनपद (राजस्व जनपद) में अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी :–

(i)–यदि वह अपने गृह जनपद में तैनात है,
(ii)–यदि उसने पिछले चार वर्षो के दौरान उस जनपद में तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हों, या दिनांक 30 जून, 2024 को अथवा उससे पूर्व तीन वर्ष पूर्ण कर रहे हों।

तीन वर्ष की सेवा अवधि की गणना करते समय, जनपद के अन्तर्गत किसी पद पर पदोन्नति की गणना भी की जायेगी।

4— यदि किसी छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इसके अनुपालन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो, वह इससे छूट प्राप्त किए जाने हेतु विशिष्ट मामले, उनके कारण सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को संदर्भित कर सकते हैं, और आयोग ऐसे प्रकरणों पर यदि आवश्यक समझे, निर्देश जारी कर सकेगा।

5—प्रयोज्यता (Applicability)

5.1—जनपद अधिकारी :—

यह निर्देश न केवल विर्निदिष्ट निर्वाचन कर्तव्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों, यथा : जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन से सम्बन्धित नोडल अधिकारी पर ही लागू नहीं होंगे, बल्कि जिला स्तरीय अधिकारियों यथा : अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, डिप्टी कलेक्टरों/संयुक्त कलेक्टरों, तहसीलदारों, खण्ड विकास अधिकारियों और निर्वाचन से सीधे जुड़े अन्य समान पदधारकों पर भी लागू होंगे।

5.2—जनद अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी :—

आयोग के उक्त निर्देश नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

5.3— पुलिस अधिकारी :—

उक्त निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों यथा Range ADGs/IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs/Sergeant Majors or equivalent rank, जो निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बल की तैनाती के लिए जिम्मेदार हों पर भी लागू होगें। कम्प्यूटरीकरण, विशेष शाखाओं, प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यात्मक विभागों में तैनात पुलिस अधिकारी उक्त निर्देशों के अन्तर्गत आच्दाछित नहीं होगें।

(i)— पुलिस सब इस्पेक्टर और उनसे उच्च पदीय अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

(ii)— यदि पुलिस सब इस्पेक्टर ने पुलिस सब—डिवीजन में 30 जून, 2024 या इससे पहले चार वर्षो में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, या पूरा कर रहा है, तो उसका ऐसे पुलिस सब—डिवीजन में स्थानान्तरण कर देना चाहिए, जो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत न पड़ती हो। यदि जिले के छोटे आकार के कारण यह सम्भव न हो तो उसे जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

5.4—निषेध और आबकारी अधिकारी (Prohibition and Excise Officers):

आयोग के यह निर्देश राज्य के निषेध और आबकारी विभाग के उप निरीक्षक या उससे ऊपर के पदधारकों पर भी लागू होंगे।

6. स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आच्छादित न होने वाले अधिकारियों की श्रेणियॉ :—

किसी भी निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन एवं सम्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की निर्वाचन ड्यूटियों के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों को तैनात किया जाता है, और आयोग की कोई मंशा नहीं है कि, बड़ी संख्या में स्थानान्तरण करके राज्य मशीनरी में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैलायी जाय। इसलिए उपुर्यक्त स्थानान्तरण नीति समान्यतः निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(i)– संबंधित विभाग के राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारी,

(ii)– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो चुनाव से सीधे संबंधित नहीं है, जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षकों/प्रधानाचार्य आदि। हालांकि ऐसे अधिकारी जिन पर अगर किसी सरकार के विरूद्ध राजनैतिक पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह की विशिष्टां जॉच करने पर सिद्ध पायी जाती है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को न केवल ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण की अनुशंसा कर सकता है बल्कि उक्त अधिकारी के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही भी कर सकता है।

(iii)–निर्वाचन ड्यूटी में सेक्टर आफिसर/जोनल आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी इन निर्देशों के अधीन आच्छादित नहीं होगें। तथापि प्रेक्षकों, सीईओ/डीईओ तथा आरओ को उनके आचरण पर सतर्क निगरानी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में गैर–पक्षतापूर्ण और निष्पक्ष रहें।

(iv)–उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की थी और जो लम्बित है या जिसकी परिणति में दण्ड दिया गया था अथवा जिन्हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, उन्हें निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जायेगी, तथापि, ऐसे अधिकारी, जो आयोग के आदेशों के अधीन किसी विगत स्थानान्तरित किया गया था, को केवल इसी आधार पर जब तक स्थानान्तरित किया गया था, को केवल इसी आधार पर तब तक स्थानान्तरित करने पर विचार नहीं किया जायेगा, बशर्ते ऐसे किसी अधिकारी के बारे में आयोग द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिए जाय। ऐसे दागी अधिकारियों का विवरण रखने के संबंध में आयोग के पत्र संख्या 646/INST/2008-EPS दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 (प्रति संलग्न) में जारी दिशा–निर्देशों का मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

(v)–उक्त के अतिरिक्त आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्ति की है कि, ऐसे किसी अधिकारी/कर्मचारी को, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित है, उन्हें निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी ड्यूटी में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

(vi)–कोई भी अधिकारी, जो आगामी छः माह के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है, को आयोग के प्रस्तर–3 में उल्लिखित निर्देशों की परिधि से बाहर रखा जायेगा। छः महीने की अवधि 30 जून, 2024 से पीछे की ओर मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त श्रेणी (गृह जनपद/3+ मानदण्ड तथा वह छः माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं) में आने वाले अधिकारी यदि पैरा 5.1 एवं 5.2 में उल्लिखित निर्वाचन

संबंधी पद पर है, तो उसे उस प्रभार से मुक्त किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की निर्वाचन ड्यूटी प्रदान नहीं की जायेगी। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को जनपद से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(vii)–राज्य के ऐसे भी अधिकारियों (मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात अधिकारियों को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है या जिन्हें विभिन्न हैसियतों से पुनः नियोजित किया गया है, निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य में तैनात नहीं किए जायेंगें।

7– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं, यदि कोई हो तो, के संबंध में स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से निर्वाचक नामावली के अन्तिम रूप से प्रकाशन के पश्चात ही किया जायेगा। किन्हीं असाधारण परिस्थिति में स्थानान्तरण की आवश्यकता के मामलों में आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8– आयोग की उपरोक्त नीति के अनुसार स्थानान्तरित अधिकारियों के स्थान पर अलग–अलग व्यक्तियों की तैनाती करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श करते हुए, इन निर्देशों के अधीन जारी स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध करीय जाय।

9– निर्वाचन संबंधी सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि, वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत करें ताकि वह तदनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकें

–: घोषणा–पत्र :–

नाम निर्देशन–पत्रों की अंतिम तिथि के पश्चात 2 (दो) दिनों के अन्दर प्रस्तुत किए जाने हेतु

मैं, ... (नाम) .... वर्तमान में .... तारीख से .... के रूप में पदस्थापित, एतद्द्वारा लोक सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि,

(क)– मैं, वर्तमान में निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन में राज्य/जिले के प्रमुख राजनैतिक पदाधिकारी का/की करीबी रिश्तेदार नहीं हूँ।

(ख)– मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

टिप्पणी :– यदि उपर्युक्त (क) और (ख) का जवाब "हॉ" है तो पूरा विवरण अलग पन्ने पर दें।
दिनांक : ....

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

टिप्पणी : किसी भी अधिकारी द्वारा की गई मिथ्या घोषणा उसे उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाएगी।

10– आयोग के उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए संबंधित विभागों/अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी या जिले के संबंधित अधिकारीगण सुनिश्चित करेंगे कि, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है, वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना तुरन्त अपना चार्ज सौंप दें।

11— आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि, उक्त दिशा—निर्देशों के अधीन आच्छादित सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती सुनिश्चित करते हुए, राज्य सरकार के संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त कार्यवाही की जानकारी एवं अनुपालन आख्या मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा विवरण सहित आयोग को 31 जनवरी, 2024 तक प्रस्तुत की जानी है।

अतः आयोग के उक्त दिशा—निर्देशों के अनुपालन में प्रभावी समुचित कार्यवाही करते हुए तद्नुसार संकलित अनुपालन आख्या **दिनांक 15 जनवरी, 2024** तक सचिव, निर्वाचन तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि तद्नुसार भारत निर्वाचन आयोग को निर्धारित अन्तर्गत अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें।

भवदीय

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 03-01-2024 13:37:31

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

(डॉ. एस.एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

By Speed Post/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023 Dated: 21st December, 2023

A CEO (Election)
१२११प्र. वि०
01/1/2024

To

1. The Chief Secretaries to all the States and Union Territories.

2. The Chief Electoral Officers of all the States and Union Territories.

Addl. CEO

Subject:- **General Elections to House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim - Transfer/Posting of officers - regarding..**

1.1.24

Madam/Sir,

I am directed to state that the term of existing House of the people (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim are upto 16th June, 2024, 11th June, 2024, 2nd June, 2024, 24th June, 2024 and 2nd June, 2024 respectively.

2. The Commission has been following a consistent policy that officers directly connected with conduct of elections in an election going State/UT are not posted in their home districts or places where they have served for considerably long period.

3. Hence, the Commission has decided that **no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district (revenue district) of posting:-**

(i) if she/he is posted in her/his home district.

Secy Karmik/Election

(ii) if she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before 30th June, 2024

While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted.

(एम.एल. उनियाल)
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

4. If any small state/UT with a few numbers of districts, face any difficulty in compliance of the above instruction, then it may refer the specific case with reasons to the Commission through CEO for exemption and the Commission would issue directions, if considered necessary.

246180/2023/0.0/(C.S)
28/12/23

A.CEO

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
1-1-24

A AOI
SO
2/1/24
ACEO
BS
SO
2-1-24

5. **Applicability**

5.1 District Officers: - These instructions shall cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy. DEOs, RO/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works.

5.2 Officers other than District Officers: - These instructions shall also cover the officers deputed in Municipal Corporations and Development Authorities, etc.

5.3 Police Officers: - These instructions shall be applicable to the police department officers such as Range ADGs/IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs / Sergeant Majors or equivalent ranks, who are responsible for security arrangement or deployment of police forces in the district at election time. The police officials who are posted in functional departments like computerization, special branch, training, etc. are not covered under these instructions. Following shall be followed:

(i) The Police Sub-Inspectors and above should not be posted in their home district.

(ii) If a Police Sub-Inspector has completed or would be completing a tenure of 3 years out of four years on or before the cutoff date in a police sub-division, then he should be transferred out to a police sub-division which does not fall in the same AC. If that is not possible due to small size of district, then he/she should be transferred out of the district.

5.4 Prohibition and Excise Officers: - Further, these instructions shall also be applicable to the officers of the Prohibition and Excise Department of the State of the rank of Sub-Inspector and above.

6. **Categories of Officers not covered under transfer policy**

During an election, a large number of employees are drafted for different types of election duty and the Commission has no intention of massive dislocation of state machinery by large scale transfers. Hence, the aforesaid transfer policy is normally not applicable to the categories of officers mentioned below:

(i) Officers posted in the State headquarters of the department concerned.

(ii) Officers/Officials who are not directly connected with elections like doctors, engineers, teachers/principals etc. However, if there are specific complaints of political bias or prejudice against any such govt. officer, which on enquiry, are found to be substantiated, then CEO/ECI may order not only the transfer of such official but also appropriate departmental action against the said officer.

(iii) The officers appointed as Sector Officer/Zonal Magistrate involved in election duties are not covered under these instructions. However, the observers, CEO/DEOs and ROs should keep a close watch on their conduct to ensure that they are fair and non-partisan in the performance of their duties.

(iv) It is further directed that the officers/officials against whom the Commission had recommended disciplinary action in past and which is pending or which has resulted in a penalty or the officers who have been charged for any lapse in any election or election related work in the past, shall not be assigned any election related duty. However, an officer who was transferred during any past election under the Commission's order without any recommendation of disciplinary actions will not be, just on this ground, considered for transfer, unless specifically so directed by the Commission. A copy of the Commission's instruction number 464/INST/2008-EPS dated 23rd December 2008 regarding tracking of names of tainted officers is enclosed. CEOs must ensure its compliance.

(v) The Commission further desires that no officer/official, against whom a criminal case related to official functioning is pending in any court of law, be associated with/deployed on election related duty.

(vi) Any officer, who is due to retire within the coming six months will be exempted from the purview of the Commission's directions mentioned in para-3. The six months period shall be reckoned backwards from 30th June, 2024. Further, officer falling in the category (home district/3 years+ criteria and due to retire within 6 months) if holding an election related post mentioned in para 5, shall be relieved of that charge and not be associated with any election related duty. It is however, reiterated that such retiring officer need not be transferred out of the district.

(vii) All the officials of the State (except those posted in the office of the Chief Electoral Officer), who are on extension of service or re-employed in different capacities, will not be associated with any election related work.

7. The transfer orders in respect of officers/officials, who are engaged in the electoral rolls revision work, if any, during an election year shall be implemented only after final publication of the electoral rolls, in consultation with the Chief Electoral Officer concerned. In case of any need for transfer due to any extra ordinary reasons, prior approval of the Commission shall be taken.

8. The Chief Electoral Officer of the State/UT shall invariably be consulted while posting the persons in place of present incumbents who stand transferred as per the above policy of the Commission. A copy of each of the transfer orders issued under these directions shall be given to the Chief Electoral Officer without fail.

9. All election related Officers will be required to give a declaration in the format given below to the DEO concerned, who shall inform to CEO accordingly.

DECLARATION

(To be submitted within 2 days after the last date of nomination papers)

I..................(Name).............presently posted ....from............(Date)
Do hereby make a solemn declaration, in connection with the current General/Bye election to Lok Sabha/..............(Legislative Assembly that...............

(a) I am not a close relative of any of the contesting candidates in the current election/leading political functionary of the state/district at the aforesaid election.

(b) No criminal case is pending against me in any court of law.

Note- If answer of (a) or (b) above is 'YES', then give full details in a separate sheet.

Dated................

(Name)
Designation

NOTE- Any false declaration made by any officer shall invite appropriate disciplinary actions.

10. The Commission's aforesaid instructions shall be brought to the notice of the concerned departments/offices or State Govt. for their strict compliance. The DEO or concerned district officers shall ensure that officers/officials who are transferred should immediately handover their charge without waiting for their substitute.

11. The Commission has further directed that transfer/posting of all officers covered under the above instructions shall be done and compliance reports by Chief Secretary and DGP with details of action obtained from the concerned departments/offices of State Government shall be furnished to the Commission by **31st January, 2024.**

12. Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SENIOR PRINCIPAL SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No 464/INST/2008/EPS Date: 23rd December 2008

To

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs

Subject Tracking the names of officers transferred by the order of the Election Commission of India charged with dereliction of duty etc.

Ref: No.437/6/2006-PLN.III dated 6th Novermber,2006 & ECI message No.100/1994-PLN.I dated 28.3.1994 addressed to the CEOs of all States & UTs

Sir/Madam,

The Election Commission of India vide the instruction referred to above had directed that a detailed review shall be undertaken before every election in all districts and all such officers should be posted out of their home districts or district where they have completed a tenure of 3 years out of 4 years, and had further directed that officers/officials against whom Commission has recommended disciplinary action or who have been charged for any lapse in election or election related work or who were transferred under the orders of the Commission in the matter may not be assigned to any election related duty

However, it was observed during recent elections that in spite of efforts made by the CEOs and the DEOs to comply the above instruction of the Commission, there were still some instances of the officers who come under the above criteria and liable to be transferred out of the district to a non election related assignment but managed to stay back and the Commission came to know about this only at a later stage through complaints being raised by various political parties and members of public. These incidents, though few in numbers, send a wrong signal at the field level and non maintenance of proper information about the officers liable to be transferred on the above criteria has been recognised as a reason for some stray incidents of non-compliance. In order to remove the possibility of the occurrence of such incidents in future, the Commission has issued the following directions to make the existing instruction more effective:-

I The CEO of the State shall maintain a register in which the information about IAS/IPS officers, DEOs, ROs and EROs transferred by the order of the Election Commission and against whom Commission has recommended disciplinary action or who have been charged for any lapse in election or election related work shall be maintained.

II Similarly, the DEO will maintain a register containing information about other junior officers and other staff.

III Within 7 days of the announcement of elections by the Election Commission of India the CEO of the State will send a compliance letter to the Zonal Secretary in the Commission confirming that all the officers coming under the above criteria have been transferred. Similarly he shall obtain a similar

ACEO

compliance certificate from all the DEOs confirming that all the officers/staff coming under the above criteria have been transferred to non-election related assignment and out of the district

IV With reference to transfer of officers coming under '3 years out of 4 years criteria' and the home district criteria, DEOs shall ensure compliance in respect of ROs, EROs, AROs and AEROs and other election related officials and send a letter to CEO within the time, if any, stipulated for this purpose by the Election Commission of India or CEO and if not, within 7 days of issue of press note announcing the elections. Similarly, information related to DEOs, SSP and SPs and other senior police officials connected with the election work shall be maintained by the CEO and compliance by the State Govt shall be ensured at his level Compliance regarding the transfer of these officers shall be collected from the DEOs and the CEO of the State shall send a consolidated letter of compliance to the Zonal Secretary within 7 days of the announcement of election.

V. To facilitate the submission of this compliance letter within 7 days of the announcement of election, the CEO and DEO shall collect the information and ensure maintenance of register as stated above well in advance so that no time is lost.

VI. There are many departments in the State Government that are involved in transferring officials and thereby accountable for the compliance of the above instructions of the Commission. The Commission's instruction regarding transfer of the officials during election shall be brought to the notice of the Secretaries of the departments concerned with a copy to the Chief Secretary. The Chief Secretary may be requested by the CEO to ensure that all the departments concerned comply with the Commission's instruction well in time.

VII. With regard to bye-elections while the officers coming under the category, dealt within para marked as (I) shall be transferred out of the district within three days of announcement of bye-election and certainly before the first days of receipt of nomination whichever is earlier.

VIII. The above instruction be followed without any deviation.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
PRINCIPAL SECRETARY